राज्यपाल व मुख्यमंत्री ''एट होम'' में शामिल, 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक दिये

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी में कला व साहित्य की प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया

उदयपुर, (कासं) 25 जनवरी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सहेलियों की बाड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शनिवार को ''एट होम'' कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान भी किया।

■ राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जनजाति विकास मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, लोकसभा सांसद, स्थानीय विधायक व संभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े शनिवार अपराह्न बाद सहेलियो की बाड़ी पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय धुन के साथ हुआ। इसके पश्चात राज्यपाल ने 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए तथा विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र दिए गए।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कला, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया।

कार्यक्रम में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, लोकसभा सांसद डॉ मन्नालाल रावत, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, जिला कलक्टर अरविन्द पोसवाल आदि मौजूद थे।

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 25 जनवरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से यह जानकारी सामने आयी है। अमेरिका की एक अदालत ने मामले में उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी, जिससे राणा के भारत प्रत्यर्पित होने से बचने का आखिरी कानूनी मौका भी खत्म हो गया। यह रिट नवंबर 2024 में निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें भारत में उसके प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्टिओरीरी रिट एक कानूनी दस्तावेज है, जो उच्च न्यायालय को निचली अदालत के मामले की समीक्षा करने की अनुमति देता है। राणा के भारत प्रत्यर्पण से मुंबई आतंकी हमलों के मामले में कई संवेदनशील खुलासे होने की उम्मीद है। 26/11 के आरोपी राणा पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली का करीबी था, जिसने मुंबई में हमले की जगहों की रेकी भी की थी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं

जयपुर, 25 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 76वें गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। शर्मा ने कहा कि गणतंत्र दिवस लोकतंत्र और संविधान में देशवासियों की आस्था का प्रतीक है। यह दिन हमें हमारे महान संविधान निर्माताओं की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान आदर्शों को संविधान के जरिए अंगीकार किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आव्हाान किया कि वे देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने तथा देश-प्रदेश की उन्नति में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लें, ताकि विकसित भारत-विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार किया जा सके।

तुरंत प्रभाव से विदेशों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीमो कहता है कि वर्तमान विदेशी सहायता के स्टॉप वर्क आर्डर तत्कालीन जारी हो जायेंगे तथा तब तक जारी रहेंगे, जब तक रुबियो समीक्षा नहीं कर लेते।

यूएस एजेन्सी फॉर इंटरनैशनल डवलपमैंट (यूएसएआईडी) के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने, अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर कहा, ''यह एक निर्मित दुर्व्यवस्था है।''

उक्त अधिकारी ने कहा, ''सभी संस्थाओं को अपनी सारी गतिविधियाँ रोक देनी पड़ेंगी तथा इसी प्रकार सभी जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं, एचआईवी/एड्स, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, सभी कृषि कार्य, शिक्षा तथा सिविल सोसायटी संगठनों की सारी सहायता रुक जायेगी।''

यूएसएआईडी के एक अधिकारी, जिन्होंने उनका नाम उजागर न करने का अनुरोध किया, ने कहा कि यूक्रेन में विभिन्न प्रोजैक्टों के जिम्मेदार अधिकारियों को सारा काम रोक देने के लिये कह दिया गया है। उस अधिकारी ने कहा कि रोक दिये गये प्रोजैक्टों में स्कूल तथा चिकित्सा सहायता, जैसे आपातकालीन मातृ-चिकित्सा तथा बच्चों के वैक्सीनेशन आदि शामिल हैं।

अगले 85 दिनों तक चलने वाली समीक्षा के बाद, क्या रुबिनो द्वारा निर्णय लिये जायेंगे कि ये सहायता कार्यक्रम जारी रहेंगे, संशोधित होंगे या रद्द कर दिये जायेंगे। उस समय तक, रुबियो ढ़ील बरतने की स्वीकृति दे सकते हैं।

मीमो के अनुसार, रुबियोने आपातकालीन खाद्य सहायता के मामलों में भी ढील दे दी है। यह ढील गाज़ा स्ट्रिप में दी गई मानवीयता की खातिर दी गई है, जहाँ इज़रायल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों ने हमास में रविवार को युद्ध विराम की शुरुआत की थी। इसके अलावा, सूडान सहित, विश्व के अन्य कई भूख-पीड़ित क्षेत्रों में इस किस्म की ढील दी गई है।

स्टेट डिपार्टमैंट के मीमो में यह भी कहागया है कि रुबियो ने इन छूटों की स्वीकृति ''इज़रायल तथा मिस्र के लिये विदेशी सैन्य वित्त-पोषण तथाउन प्रशासनिक खर्चों, जिनमें वेतन शामिल हैं, जो विदेशी सैन्य वित्त-पोषण के संचालन के लिये आवश्यक हैं।

फॉरेन मिलिट्री फायनेंसिंग के रूप में, इज़रायल को करीब 3.3 अरब डॉलर तथा मिस्र को करीब 1.3 अरब डॉलर मिलते हैं।

2025 में इस प्रकार की फायनेंसिंग के लिये चिन्हित किये गये अन्य देश हैं- यूक्रेन, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लैटविया, लिथूनिया, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलिपींस, थाइलैंड,ख वियतनाम, डीजीबोती, कोलम्बिया, पनामा, इक्वेडोर, इज़रायल, मिस्र तथा जॉर्डन। इसके लिये पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन सरकार ने कांग्रेस से अनुरोध किया था।

इस अनुरोध में यह भी कहा गया था कि फॉरेन मिलिट्री फायनेंसिंग ''लिबनान की सशस्त्र सेनाओं की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेगी, ताकि वहाँ अस्थिरता की संभावना कम हो तथा ईरान के दुष्प्रभाव का प्रतिकार किया जा सके।'' लिबनान की सेना इस समय देश के दक्षिण में तैनात होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इज़रायली सेनाएं युद्ध विराम समझौते के तहत वहाँ से हट रही हैं। इस समझौते के अनुसार, ईरान-समर्थक हिज़बुल्लाह हथियार और लड़ाकू भी उस क्षेत्र से हटाये जाने हैं।

मध्य प्रदेश में शराबबंदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गुजरात शामिल हैं, को लेकर भारी चिंता जताई जाती है, क्योंकि वहाँ शराब का बड़ा बाज़ार पनप रहा है, जहाँ प्राय: खतरनाक और मिलावटी शराब की बिक्री होती है।

दूसरी तरफ, राज्य सरकारों को राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होता है तथा इसे लागू करने पर सवाल खड़े होते रहे हैं तथा इसे लागू करने पर सवाल खड़े होते रहे हैं तथा भ्रष्टाचार तथा पुलिस-प्रताड़ना के आरोप भी लगते रहे हैं।

जहाँ बिहार जैसे राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू है, वहीं गुजरात विदेशियों तथा भारत के अन्य भागों से आये हुये लोगों को यह अनुमति देता है कि वे शराब खरीदने के लिये परमिट हेतु ऑनलाइन आवेदन करें तथा राज्य के 35 रजिस्टर्ड स्टोरों में से किसी से भी शराब खरीद लें। नागालैंड में 1989 में शराब की बिक्री और उपभोग पर रोक लगा दी थी, लेकिन रोक में ढ़ील दी जा चुकी है तथा राज्य में ''भारत निर्मित विदेशी शराब'' खुले रूप में उपलब्ध बताई जाती है। कांग्रेस ने इस मद्य-निषेध नीति को ''पूरी तरह विफल'' बताया है तथा कहा है कि इसे हटा लिया जाये।

आंध्र प्रदेश ने 1952 में शराबबंदी का प्रयोग किया था तथा उसके बाद एक बार 1994 में भी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने 1997 में इसे यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि सीमा पार से तथा राज्य के अंदर होने वाली लीकेज़ के कारण, शराबबंदी सफल और व्यवहार्य नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इससे पहले उमा भारती तथा शिवराज सिंह के कार्यकालों में शराबबंदी लागू करने की कोशिशें की जा चुकी है।

इस सप्ताह साठ वर्ष पूर्व चर्चिल की मृत्यु...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रूप में छवि बहुत बड़ी थी, और पाश्चात्य जगत के लोग उन्हें ''स्वतंत्र विश्व'' को बचाने वाले प्रचारित करते है लेकिन क्लैमेंट एटली उस समय की जरूरतों को समझने में सक्षम था।

चर्चिल जब बहुत युवा थे तब ही से भारत के प्रति उनकी एक सोच विकसित हो गई थी। उन्होंने ब्रिटिश काल में बतौर पत्रकार यहा काम किया। उन्होंने भारतीय सीमाओं पर लड़े गए कई युद्धों के बारे में लिखा। कोलकाता में उन्होंने तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन से मुलाकात की इसके बाद वे ब्रिटेन लौट गए।

जब चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ मित्र देशों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उस समय 1942 में बंगाल भी जब अकाल से जूझ रहा था और ये चर्चिल ही थे, जिन्होंने उस अकाल को भीषण त्रासदी में बदल दिया था क्योंकि उन्होंने बंगाल के लिए भेजे जा रहे अनाज के जहाजों को मित्र देशों की सेनाओं के लिए भेज दिया था और लाखों भारतीय भूख से मर गए थे।

■ यह भी सोच अब पनप रही है कि जर्मनी पर, यहूदियों को ''कन्सन्ट्रेशन कैम्प'' आदि में की गई हत्याओं के कारण, ''वार क्राइम्स'' (युद्ध के अपराधों) के अंतर्गत मुकदमा चल सकता है, तो बंगाल में हुई भुखमरी के लिये चर्चिल व इंगलैंड पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जा सकता।

ऐसा नहीं था कि मित्र देशों की सेना भोजन के संकट से जूझ रही थी या उन्हें पर्याप्त राशन नहीं मिल रहा था, चर्चिल ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि कहीं मित्र देशों की सेनाओं को अकस्मात अनाज की जरूरत पड़ जाए। चर्चिल का वह युद्ध अपराध बहुत बड़ा था पर इस पर इसलिए ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अकाल और भूख से मरने वाले लाखों भारतीय असहाय थे।

भारत के लिए 1942 बेहद कठिन समय था, जिसे चर्चिल ऐसा सुनहरा समय बता कर प्रचारित कर रहे थे जो हजारों सालों में एक बार आता है। यह समय है कि भारत को उन लोगों की याद में एक स्मारक बनाना चाहिए जो चर्चिल निर्णय (अन्यायपूर्ण निर्णय) की वजह से भूख से मारे गए थे। जिस अनाज की उस समय भारतीयों को सख्त जरूरत थी वह चर्चिल ने मित्र देशों की सेनाओं को दिलवा दिया।

युद्ध खत्म होने के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के युद्ध अपराधों पर विचार किया, जहां लाखों यहूदी व अन्य लोग यातना शिविरों व गैस चैम्बरों में मार डाले गए थे, पर उन्होंने भारत में भूख से मरे लाखों लोगों का कारण बने एक अपराध पर कभी भी विचार नहीं किया।

युद्धकाल में अगर चर्चिल को कोई व्यक्ति नापसंद था तो वह थे महात्मा गांधी जो चर्चिल एकदम विपरीत थे। गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य की ''सिविलाइज़्ड फोर्स'' होने की धारणा को अस्वीकार कर दिया और चर्चिल को यह अस्वीकृति कतई पसंद नहीं थी।

प्रशिक्षित सैनिक चर्चिल ब्रिटिश समाज के पारम्परिक समाज और रूढिवादी परम्पराओं साथ पले बढ़े थे। इसके विपरीत गांधी ने ताकत को अंतिम परीक्षण के रूप में नकार दिया था। गांधी की राजनीति चर्चिल को स्त्रियोचित लगती थी। चरखा चलाने को चर्चिल औरतों का काम मानते थे।

क्लेमैंट ऐटली को श्रमिक नेता के रूप में चर्चिल ने उपप्रधानमंत्री बनाया था। ऐटली ने कई बार चर्चिल की सहायता की थी ऐटली एक जाने वाले वकील के बेटे थे वे 1920 के दशक में भारत आए थे और स्वतंत्रता संग्राम को उन्होंने खुद देखा था।

अगर 1947 में ऐटली ने भारत छोड़ने की प्रक्रिया तेज नहीं की होती तो भी भारत ब्रिटेन से आज़ादी छीन लेगा। भारतीय इतिहासकारों को सत्ता हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और इसमें ऐटली की भूमिका को विस्तार से देखना चाहिए। यह नए सिरे से पुर्नमूल्यांकन करने का समय है।

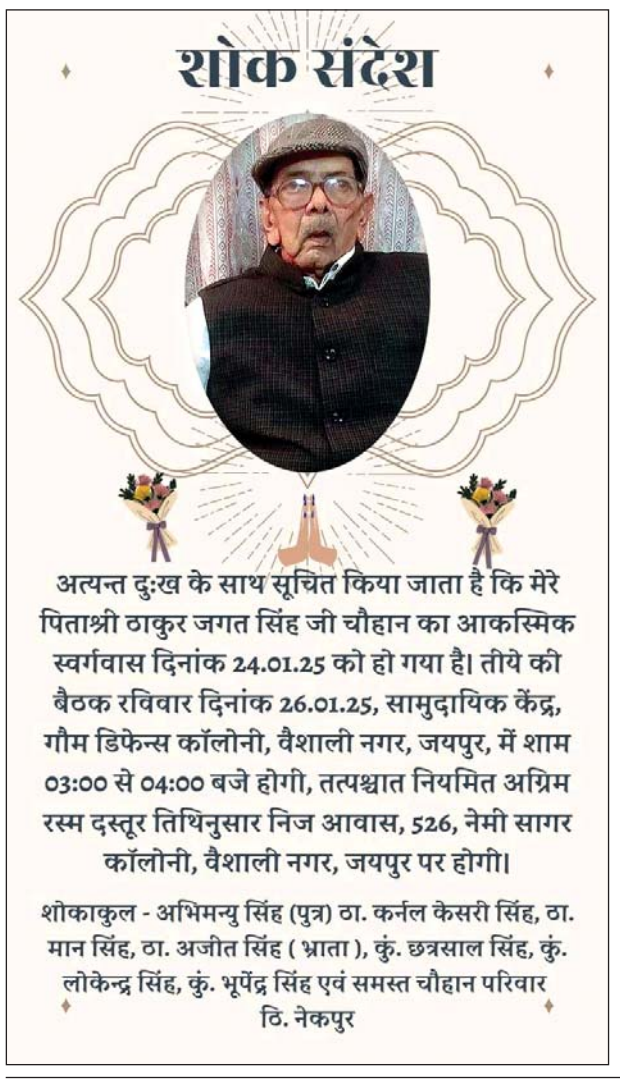

ट्रम्प द्वारा चयनित नये...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिंता व्यक्त की है। उनका तर्क है कि इससे आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी को और ज्यादा आधुनिक बनाने, परमाणु निरोध के प्रबंध, उभरते वैश्विक खतरों का मुकाबला करने और रणनीतिक रक्षा पहलों को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

डिफैन्स सैक्रेटरी की भूमिका अमेरिकी प्रशासन में कितनी महत्वपूर्ण और गंभीर है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सैन्य कमान श्रृंखला में रक्षा सचिव राष्ट्रपति के बाद दूसरे स्थान पर होते हैं। यहाँ तक कि सबसे उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी, संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष को भी सैन्य संचालन करते समय रक्षा मंत्री के माध्यम से ही राष्ट्रपति को जानकारी देते है।

रक्षा सचिव वाइट हाउस और कांग्रेस के साथ मिलकर व्यापक विदेशी नीति के तह पहलों को विकसित करता है। सभी सैन्य विभाग एकीकृत होकर पेंटागन में एक एकल इकाई के रूप में कार्य करते हैं, जो देश का सैन्य मुख्यालय है। रक्षा विभाग के मुख्य कार्यकारी के रूप में, रक्षा सचिव पेंटागन में सभी संचालन की निगरानी करते हैं।

इसके अतिरिक्त, चूंकि सशस्त्र सेवाएं केवल युद्ध नहीं करतीं, रक्षा विभाग में मजबूत खुफिया संचालन भी होते हैं और ये जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) को रिपोर्ट की जाती है। रक्षा सचिव इस खुफिया जानकारी को समन्वित करने में मदद करते हैं।

इसके अलावा हैगसेथ महिलाओं के युद्ध में भाग लेने के खिलाफ बयान दे चुके हैं जिसके लिए उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। सेना में स्त्री-पुरुष समानता पर उनके विचारों पर चिंता व्यक्त की जा रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, नए रक्षा सचिव पर भारी शराब पीने और महिलाओं के प्रति आक्रामक व्यवहार करने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें 2017 का एक यौन हमले का आरोप भी शामिल है, जिसे उन्होंने कोर्ट के बाहर निपटाया।

कश्मीर में पहली वंदे भारत ट्रेन का सफल ट्रायल सम्पन्न

श्रीनगर, 25 जनवरी। शनिवार को कटरा में माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से मध्य कश्मीर तक पहली वंदे भारत ट्रेन के सफल परीक्षण के साथ कश्मीर के लिए ट्रेन का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना आखिरकार वास्तविकता के करीब है। उम्मीद है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी अगले महीने इस सेवा का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद कश्मीर के लिए बहुप्रतीक्षित ट्रेन आधिकारिक तौर पर परिचालन शुरू हो जाएगी।

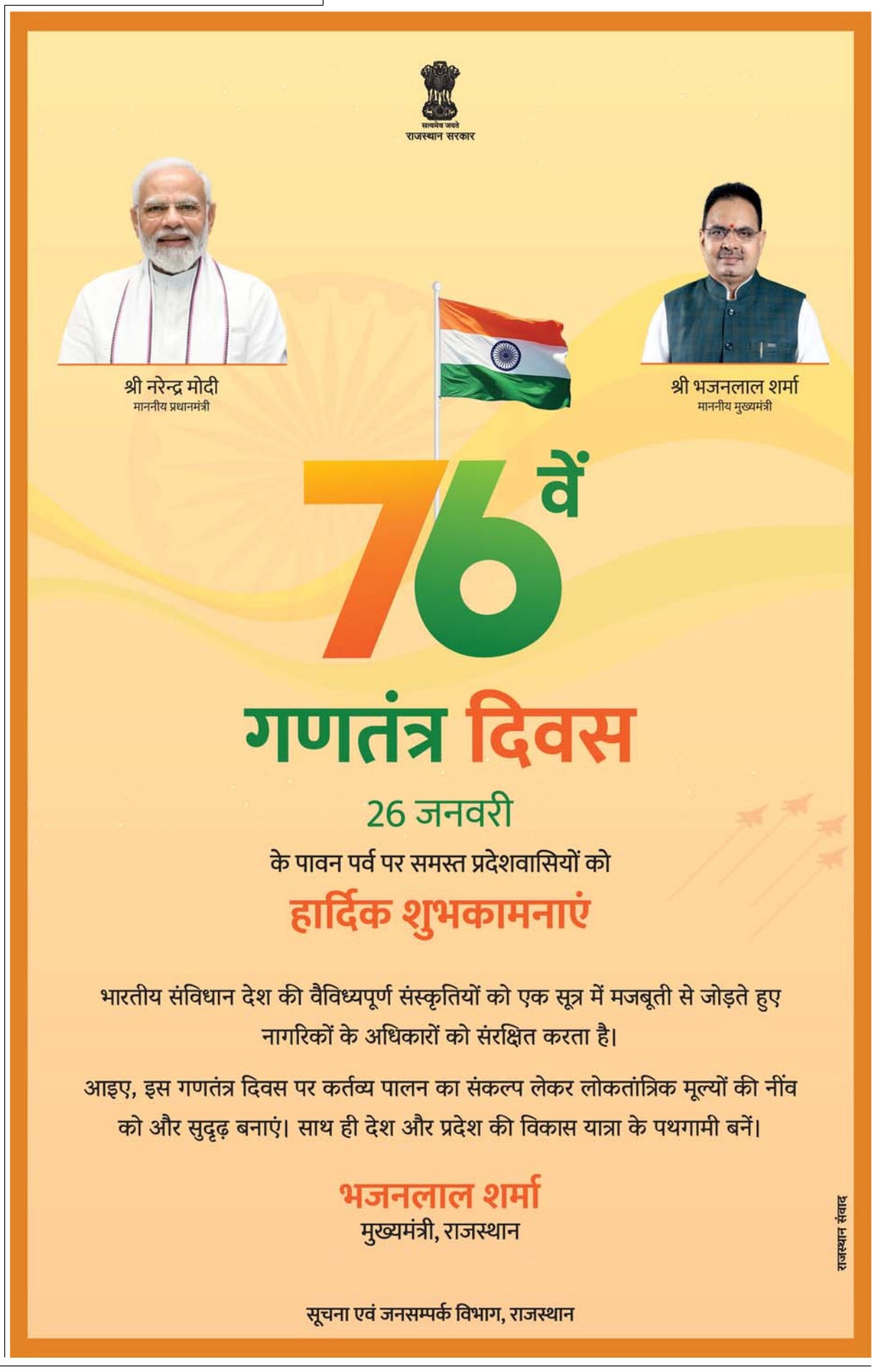

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908